संख्या-140/2019/3873/41-2018-40 यो0/2013 टी0सी0

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 29 मार्च, 2019**

विषय:-जनपद मथुरा में ऐतिहासिक एवं धार्मिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की चालू प्रायोजना (फेज-3) के अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु अग्रतर वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5317/6-1-1(405)/2017-18, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद मथुरा में तृतीय फेज के अन्तर्गत 10 ऐतिहासिक जलकुण्डों (1) चन्द्र कुण्ड (छाता) (2) बलभद्र कुण्ड (बड़ी बठैन) (3) कृष्ण कुण्ड (छोटी बठैन) (4) बलभद्र कुण्ड (अडिंग) (5) महदर कुण्ड (गठौली) (6) सखी कुण्ड (सकीतरा (7) शाही तालाब (दौताना) (8) पय सरोवर (पयगाम) (9) पाण्डव गंगा (बैठन) (10) रत्न कुण्ड (गोवर्धन) के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास कार्य की प्रायोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुमोदित लागत रू0 1198.40 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-49/2016/371/41-2016-40 यो0/13 टी0सी0 दिनॉक 28.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त प्रश्नगत प्रायोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-123/ 2016/1962(1)/41-2016-40 यो0/टी0सी0 दिनॉक 09.12.2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-27/ 2018/20/41-2018-40 यो0/13 टी0सी0 दिनॉक 19.03.2018 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अनुमोदित लागत रू0 1198.40 लाख के सापेक्ष अब तक रू0 900.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. अत: **उपर्युक्त के क्रम में जनपद मथुरा में ऐतिहासिक एवं धार्मिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की चालू प्रायोजना (फेज-3) के अवशेष** कार्यों को कराये जाने हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में रू०2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित उक्त शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है। प्रायोजना हेतु अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहें कार्यों के निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा रही धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/ 2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

(10) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन का होगा। प्रायोजना की अन्तिम धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब द्वितीय किश्त की अवमुक्त की जा रही धनराशि का 75 प्रतिशत का उपभोग कर लिया जायेगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संगत प्रपत्रों में फोटोग्राफ सहित सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-2 में अवमुक्त की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-22-मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-140/2018/3837(1)/41-2018-40 यो0/2013 टी0सी0 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, आगरा/ जिलाधिकारी, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. पिरयोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0, यूनिट-32, अलीगढ़।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in